बर्षः- 05
अंकः- 289
मुरादाबाद
(Wednesday)
11 February 2026
पृष्ठः-8
मूल्यः- 3.00 रूपया

दैनिक
प्रातः कालीन

क्यूँ न लिखूँ सच

मुरादाबाद से प्रकाशित
भारत सरकार से रजिस्टर्ड
RNI No.UPBIL/2021/83001
राष्ट्रीय हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा,बहराइच, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

CM योगी बोले- कयामत के लिए जीने वालों कायदे से रहो अब बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनेगी, ये सपना नहीं होगा पूरा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग कयामत का दिन आने का इंतजार कर रहे हैं। वो कयामत के लिए न जिएं। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाजपा सरकार रुकने वाली नहीं है। ये सरकार जितना बोलती उतना करती है। उतना ही बोलती है जितना करती है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे है वह दिन आने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद अब कभी भी नहीं बनने वाली है। हम अपनी विरासत को यूं ही मजबूत करेंगे। याद करिए 500 साल बाद अयोध्या में गौरवपूर्ण क्षण आया। कितनी सरकारें आई कितनी गईं। कितने राजा महाराजा हुए मगर अयोध्या में राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया। राम सबके है।उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अवसरवादी रवैया अपनाकर संकट में राम को याद करते हैं। बाकी राम को विस्मित कर देते हैं इसलिए अब भगवान राम उनको भूल चुके हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि कयामत के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। कानून मानोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं तो आगे का रास्ता सीधा जहन्नुम जाता है। कानून तोड़ने वाले जहन्नुम जाएंगे। हर भारत वासी का एक ध्येय एक भारत श्रेष्ठ भारत हो। हमारा देश वैभवशाली हो। विकसित हो।हर संत देश के लिए है और धर्म भी देश के लिए है। धर्म और देश एक आत्मा और शरीर है। भारत और सनातन एक दूसरे के पूरक है। सीएम योगी मंगलवार को दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में दुल्हदेपुर स्थित बाबा हरिशंकर दास की कुटी पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दोपहर करीब सवा दो बजे सीएम का हेलीकॉप्टर कुटी के पास उतरा। यहां महंत बलरामदास ने उनका स्वागत किया। यहां पहुंचकर उन्होंने कथा मंडप का उद्घाटन किया और रामार्चा यज्ञ में आहुतियां अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कुटी परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया।

संक्षिप्त समाचार

अब एआई-जनित सामग्री की देनी होगी स्पष्ट जानकारी, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी किया आदेश

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के के लिए आदेश जारी किया कि वे एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाएं, गैरकानूनी, यौन शोषण वाली या धोखाधड़ी वाली एआई सामग्री रोकने में मदद मिल सके।केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (वाटरमार्क) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता।सरकार ने कहा कि अब मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी को स्पष्ट रूप से पहचान योग्य लेबल के साथ दिखाना अनिवार्य होगा। इसमें ऑडियो, वीडियो, फोटो या ग्राफिक सहित किसी भी डिजिटल सामग्री को शामिल किया गया है, जिसे कंप्यूटर या किसी संसाधन से बनाया गया, संशोधित किया गया या बदला गया हो।सामग्री के गैरकानूनी इस्तेमाल पर रोक सुनिश्चित करें प्लेटफॉर्म-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी यूजर ऐसी सामग्री का गलत इस्तेमाल न करे। अगर कोई यूजर गैरकानूनी, अश्लील, धोखाधड़ी या बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बनाए या साझा करे

अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर राहुल गांधी ने ही नहीं किए हस्ताक्षर, पार्टी ने बताई ये वजह

लोकसभा में विपक्षी सांसदों को न बोलने देने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। हैरानी की बात ये है कि विपक्ष राहुल गांधी को सदन में न बोलने देने का आरोप लगा रहा है और राहुल गांधी ने ही स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं!लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने लोकसभा सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। यह नोटिस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में न बोलने देने के आरोप में लाया जा रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ही इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया कि स्पीकर को पद से हटाने के नोटिस पर नेता प्रतिपक्ष का हस्ताक्षर करना संसदीय लोकतंत्र में सही नहीं है। इसी वजह से राहुल गांधी ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला किया। विपक्ष के 118 सांसदों ने किया नोटिस पर हस्ताक्षर विपक्ष के 118 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में कांग्रेस, डीएमके, सपा के सांसद शामिल हैं। नोटिस में विपक्ष ने कहा है, लोकसभा स्पीकर लगातार विपक्षी सांसदों को जनहित के मुद्दे उठाने से रोक रहे हैं। नोटिस में बताया गया कि अनुच्छेद 94(सी) के तहत नोटिस दिया गया है क्योंकि स्पीकर खुलेआम पक्षपात कर रहे हैं। विपक्ष के आठ सांसदों को मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया है; उन्हें केवल लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए दंडित किया जा रहा है। कई मौकों पर विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने की अनुमति ही नहीं दी गई, जबकि यह उनका मौलिक अधिकार है।

कांग्रेस सांसद और चीफ व्हिप के सुरेश ने लोकसभा सचिवालय को यह नोटिस दिया। टीएमसी के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और न ही वे इस नोटिस का हिस्सा हैं। विपक्ष ने इन आरोपों के चलते दिया नोटिस-विपक्ष ने जो आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, उनमें विपक्षी सांसदों को जनहित के मुद्दे उठाने से रोकना प्रमुख है।

बीती 2 फरवरी को राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख की किताब के हवाले से केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे।

सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। विपक्ष का आरोप है कि इसके बाद राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया।

विपक्ष ने स्पीकर पर सदन के संचालन में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का भी आरोप लगाया।

स्पीकर द्वारा विपक्ष के आठ सांसदों को भी पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है।

विपक्ष ने स्पीकर के इस कदम को मनमाना बताया और इसका विरोध किया।

विपक्ष ने ओम बिरला के उस बयान पर भी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 फरवरी को कई कांग्रेसी सांसद पीएम मोदी की सीट की तरफ बढ़े थे और कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन टाल दिया गया। विपक्ष का कहना है कि ये कांग्रेस सांसदों के खिलाफ फर्जी आरोप हैं।

बजट पर चर्चाः अमेरिका से डील नहीं, ढील हुई, बजट में यूपी के लिए कुछ नहीं, अखिलेश यादव का सरकार पर हमला

बजट पर चर्चा के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट आने से पहले और बाद में अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड डील करने का दावा किया है, लेकिन अब सवाल यह है कि कितने देश बचे हैं जिनसे ऐसी डील नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट पर बोलते हुए सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ हुए कथित %डील% और बजट की प्राथमिकताओं पर सरकार को घेरा। यादव ने कहा कि यह डील नहीं बल्कि ढील साबित हुई है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था और किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ञअखिलेश यादव ने बजट आने से पहले और बाद में अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड डील करने का दावा किया है, लेकिन अब सवाल यह है कि कितने देश बचे हैं जिनसे ऐसी डील नहीं हुई है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इस डील के बाद रुपये की स्थिति क्या होगी और पूछा कि अगर यही डील करनी थी तो पहले क्यों नहीं की गई। उनके अनुसार, यह डील देश के लिए कोई बड़ा लाभ नहीं बल्कि एक प्रकार की ढील है, जिससे देश को यह तय करना होगा कि 18 बड़ा है या जीरो, और बजट पहले बना या डील पहले हुई। बजट की दिशाहीनता और उपेक्षित वर्ग- यादव ने वर्तमान बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि इसमें गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इतने बड़े बजट लाए जा रहे हैं, तो भी प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से फ्री राशन पाने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय बताने की मांग की। उत्तर प्रदेश के लिए विशेष योजनाओं का अभाव- उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए बजट में किसी खास योजना का उल्लेख न होने पर भी अखिलेश यादव ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री होने के बावजूद, भारत सरकार के बजट से कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं बना है। जो एक्सप्रेसवे बने भी हैं, वे विकसित भारत की गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाया और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बन रहे एक्सप्रेसवे का नाम बदले जाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बस कागजों पर ही बन रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने के वादे पर संशय- किसानों की आय दोगुनी करने के सरकारी वादे पर भी अखिलेश यादव ने प्रश्नचिह्न लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से हुई %डील% के बाद किसानों का भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि सब कुछ विदेश से आयात होने पर किसान क्या उगाएगा और क्या बेचेगा। सरकार द्वारा एग्री इंफ्रा और मंडियों को तैयार करने की बात कहने के बावजूद, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी आज तक नहीं मिली है। उन्होंने हर्टिकल्चर क्रॉप्स और दुग्ध उत्पादन के आंकड़े गिनाने पर सरकार को घेरते हुए पूछा कि एमएसपी की गारंटी कब दी जाएगी।

किताब पर जनरल नरवणे की पहली प्रतिक्रिया, पेंगुइन के बयान को सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

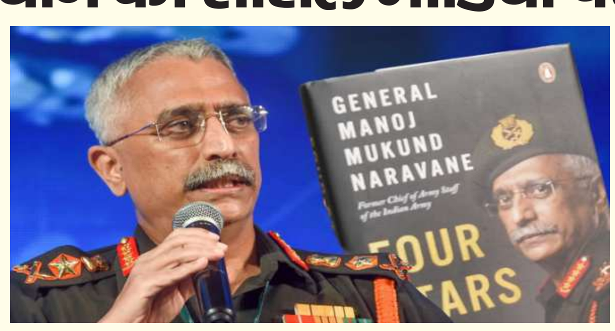

पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी पुस्तक फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। जनरल नरवणे ने इस संबंध में पेंगुइन इंडिया की ओर से जारी बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। इसी बीच पूर्व सेना प्रमुख ने मंगलवार को विवाद पर विराम लगा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किताब से संबंधित प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के आधिकारिक बयान को रीपोस्ट किया। इससे पहले प्रकाशन ने कहा था कि कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति ''मुद्रित या डिजिटल रूप में'' प्रकाशित, वितरित, बेची या किसी अन्य तरीके से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब पेंगुइन इंडिया के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए जनरल एमएम नरवणे ने एक्स पर लिखा कि किताब की वर्तमान स्थिति यह है। इसी बीच प्रकाशन की ओर से एक अन्य बयान भी जारी किया गया है। जिसमें प्रकाशक ने कहा है कि किसी किताब या उसके प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होने की घोषणा को पब्लिकेशन नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ पब्लिकेशन हाउस ने कहा है कि प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध किताब और पब्लिश हुई किताब एक ही बात नहीं हैं।पेंगुइन ने बयान में कही थी यह बात

'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया' (पीआरएचआई) ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के संस्मरण 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' की अनधिकृत प्रतियां उपलब्ध होने की खबरों के बीच कहा है कि इसके प्रकाशन का अधिकार केवल उसके पास है और यह पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रकाशन ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा था कि पुस्तक की मुद्रित या डिजिटल- किसी भी रूप में कोई भी प्रति जारी नहीं की गई है। प्रकाशक ने एक बयान में कहा, ''पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया यह स्पष्ट करना चाहता है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे द्वारा लिखित आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के प्रकाशन अधिकार केवल हमारे पास हैं। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुस्तक का प्रकाशन अब तक नहीं हुआ है। बयान में कहा गया है कि कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति ''मुद्रित या डिजिटल रूप में'' प्रकाशित, वितरित, बेची या किसी अन्य तरीके से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रकाशक ने यह भी चेतावनी दी कि वर्तमान में प्रसारित हो रहे पुस्तक के संस्करण को कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा।' कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर इस पुस्तक की एक प्रति दिखाते हुए देखा गया था।पेंगुइन इंडिया ने आज भी जारी किया बयान-पेंगुइन ने अपने बयान में कहा %एक घोषित किताब, प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध किताब और प्रकाशित किताब तीन अलग-अलग चीजें हैं। केवल घोषणा का मतलब है कि किताब भविष्य में प्रकाशित की जाएगी। प्री-ऑर्डर केवल पाठकों और रिटेलरों को अग्रिम आदेश देने की सुविधा देता है, इसका मतलब यह नहीं कि किताब पहले से ही उपलब्ध है।% साथ ही उन्होंने कहा कि प्रकाशन की निर्धारित तिथि केवल योजना का संकेत है, किताब बाजार में तभी उपलब्ध होती है जब इसे खरीदने के लिए रिटेल चैनलों पर रखा गया हो। पेंगुइन ने पहले कहा था कि किताब के प्रिंट या डिजिटल रूप में कोई संस्करण प्रकाशित, वितरित या बेचा नहीं गया है।

संपादकीय Editorial

And how many more caravans?

MP Anurag Thakur's fortunes once again rose on the cricketing horizon when the Honorable Supreme Court lifted nine years of restrictions. For the MP, this was not just a legal battle, but also a testament to the multifaceted nature of his personality. Clearly, the horizons that were closed in 2017 are now opening up in 2026, though he remains untouched by cricket in this era. From bringing cricket to Himachal to successfully decorating Parliament with Himachal cricket, these are achievements that have seen Anurag Thakur play a significant role on the national and BJP stages. He is currently the senior-most MP from Himachal, and as such, political dynamics in the state are also dictated by his influence. He is a key figure in the eyes of the high command, having been established as a cabinet member through party positions. It's a different story: his journey in state politics has faced every possibility of uncertainty, and continues to do so. He becomes the President of the BCCI, the future of the BJP on the national stage, and as a minister, he teaches economics to the nation. The very Nitin Navin he inducted into his team as the National President of the BJP Yuva Morcha, has now become the party's National President. It goes without saying that he has been considered a political icon of the BJP's young brigade, or the next generation, so why is his reputation so lost in Himachal? He is now a key figure in many of the government's secret and declared missions on the national stage, and the ultimate leader of Prime Minister Narendra Modi's Young Changemakers campaign. The importance of MP Anurag Thakur, who has become the face of this campaign's recognition for 100,000 young people, cannot be overlooked. The question now is whether he will be a key figure in the 2027 Himachal Assembly elections or prove himself in his next term in Parliament a year later. Currently, the streets of Himachal are being loudest with the influence of former Chief Minister Jai Ram Thakur. Despite this, the BJP, approaching the election threshold, is increasing its success stories. In such a scenario, a front row is being formed for the next government, where Jairam Thakur's activism, Jagat Prakash Nadda's background, and Anurag Thakur's ascendancy are being weighed. While the political scales often shift, and it's impossible to predict who will outweigh who, Anurag has so far succeeded in carving out his own niche within the political landscape. If Thakur, leading a group of BJP MPs on Himachal's economic crisis, achieves a breakthrough, or if he is offered a national position, this man can take his caravan anywhere. Whether Anurag ascends to a central role from Himachal or Jairam Thakur's fortunes shine in his second term will be determined by the twists and turns of the next two years. If key figures in Himachal's political landscape are drawing closer to Jairam Thakur, or if he is the leader of the ruling party versus the opposition, then Thakur has given new initiatives to the old caravans and new resolve to the new caravans. A new attempt to arm the opposition against the ruling party has recently been witnessed, with Kangra playing a central role, with numerous camps, platforms, and fronts being established under the leadership of Jairam Thakur. In such a scenario, the BJP remains silent even as it uses Jairam in the state and Anurag in the country, as there is always a difference between what the party says and

The one-child trend is gaining momentum, the country should not face the same situation as China and Japan.

Surveys in Delhi show that women now want children after the age of 30, leading to an increase in the number of mothers aged 30-35. Marriage and childbearing are being delayed due to the focus on education, career, and health. The one-child trend is also increasing due to the cost of parenting. Citing the experiences of China and Japan, the author expresses concern about future demographic challenges in India, where a young population may be depleted. Women now want children after the age of 30. Career, education, and health are delaying motherhood. The one-child trend is increasing, raising demographic concerns. A recent survey of women in Delhi revealed that women now want children only after the age of 30. Another survey conducted in 2024 revealed that one in four children was born to a woman over the age of 30. The number of mothers aged 30 to 35 increased from 2.7 percent to 8.9 percent between 2005 and 2024. The number of women becoming mothers between the ages of 20 and 24 decreased to 27.1 percent in 2024. It has long been believed that women are not suitable for motherhood after 30, but times have changed. Women now want to study, work, and change jobs for advancement. They are also increasingly focused on their health. Marriage is no longer a priority for them. Even if they do marry, it is late. Once upon a time, if a girl reached 30, it was assumed that she would never get married, or how, because boys do not remain single until this age. But now, marriages are increasingly taking place after 30. A major reason for this is increasing urbanization. Then, after marriage, these people don't want children right away. They first want to settle into a new lifestyle, then think about children. These days, the trend of having one child has also increased among the middle class. This is because raising children is expensive. Even if both parents earn, it is said that a child's care and education alone consumes a full salary. The old perception about having one child was that a child feels very lonely and lacks companionship throughout life. Now, even if one has a daughter, it is no longer the case that if one has a son, one definitely wants a son. A few days ago, a newspaper interviewed parents who have a son or a daughter. These parents reported that their single child never faced any problems; rather, they learn to live life quickly, do their own work, and are more disciplined. It hasn't been long since the generation in our country when having five or six siblings in a household was commonplace. The sole source of income in the household was the father, the breadwinner. Even after studying in government schools, children could find decent jobs. They were often married before 30. In those days, a working woman was often considered a woman who had suffered a disaster. A woman's education wasn't about her job or self-reliance, but rather, it was believed that if she were married off to a distant country, she could at least write letters to inform them of her well-being. Then came a period when the country was flooded with women being killed in the womb through ultrasound. Although the government has banned female foeticide, reports of such cases still surface occasionally. However, as girls became educated and progressed, they shattered the stereotypes created for themselves. Since International Women's Year was celebrated in 1975, women's issues have been increasingly addressed here. Greater emphasis was placed on their education and self-reliance. Marriage and children became a priority. Today, whether you ask a wealthy woman or a poor woman, everyone agrees that they want to study first, get a job, and only then think about marriage. Slogans like "Hum Do Hamare Do" (We Two, Our Two) are no longer heard. From a woman's perspective, it seems appropriate to have one child, but given the global situation, India may also face the same fate in 50 years. China once had the largest population in the world. Its government strictly enforced the one-child policy. What is the situation in that same China now? There is a constant shortage of youth and an increasing number of elderly people. Therefore, the government is offering various incentives to young people. More holidays and special packages are being offered to encourage young people to date, get married, and have children. Maternity leave is being extended. Fathers are also being given leave, but young people, especially women, do not want children. They are not falling for any of the government's inducements. The same situation is in Japan. Fewer children are being born there too. The same is true in many European countries. In Russia, the government announced that any woman who gives birth to ten children will be called a Mother Heroine and awarded a prize of ten million rubles. No matter what the leaders say, people are not listening. Women, in particular, are saying that they are like child-bearing machines! After all, all the discussions about women have made them so aware that they are thinking first about their own happiness and joy rather than about having and raising children. The number of couples who do not want children at all is increasing, both globally and in our country.

Tech companies should be held accountable, the digital world is ruthless.

This article focuses on the 'right to be forgotten' in the digital age, explaining how old digital footprints can become a hindrance for individuals. It highlights misuses of digital media such as fake news, doxing, and deepfakes, and emphasizes the accountability of tech companies. India needs a clear law that balances individual privacy and public interest, while advocating for the positive use of AI and a strong legal framework. Digital footprints negatively impact individuals' current lives. Threats like fake news, doxing, and deepfakes pervade the digital world. The 'right to be forgotten' and the accountability of tech companies are crucial. When we unlock our smartphone screens with the first rays of dawn, we don't just open a device, but enter a world that never sleeps. This digital world is as dazzling as it is ruthless. Today, a large part of our lives is spent within the corridors of digital media. Our identity, relationships, and social standing are now determined by our digital footprints, but the problem begins when these footprints become a burden to our current identity. Imagine a young man who was accused of a minor crime ten years ago. The court acquitted him honorably, but today, when a company Googles his name to hire him, the news of that old arrest flashes first. This is the point where the right to be forgotten becomes not a luxury but a part of the right to life. The misuse of digital media has become epidemic today. Fake news, trolling, and cyberbullying have turned the virtual space into a battlefield. The most horrific form is when someone's personal information or photos are made public without their consent. This is called doxing. This is not just a misuse of technology, but a direct attack on a person's dignity. Once offensive content goes viral, it becomes nearly impossible to completely erase it. Nothing dies permanently in the digital world; it simply remains buried and resurfaces from time to time. This is where the concept of the right to be forgotten offers a ray of hope. Individuals should have the right to have their old, irrelevant, or inaccurate digital records removed. A European Union law is a precedent in this regard. A controversial case there determined that information no longer relevant must be removed from search results. This right has gained momentum in India as well. While the Supreme Court recognized privacy as a fundamental right in the Puttaswamy case, the right to be forgotten remains shrouded in legal confusion. The Delhi High Court recently recognized that individuals have the right to move on from past mistakes or disputes. Do we have a concrete law for this? India's Digital Personal Data Protection Act, 2023, is certainly a step in this direction. It grants the right to delete data, but it faces several hurdles. When someone demands the deletion of their data, they face the barrier of freedom of expression and judicial transparency. For example, can a corrupt leader claim that people should forget their past scandals because they have now reformed? Absolutely not. The public's right to know and the public interest will always trump personal privacy, but why should an ordinary citizen who has been the victim of a false lawsuit or personal dispute have to go through the courts? Our current laws lack a clear process to hold tech companies accountable. AI has now entered this complex equation. Deepfakes are the most horrific form of AI misuse. Today, combining an ordinary person's face with a pornographic video or inflammatory speech has become child's play. AI algorithms are so powerful that they can sense your likes and dislikes and steer you in the direction they desire. Hateful content receives more engagement, so the algorithms promote it. This is the face of AI that is dividing society. The solution lies within AI itself. If we use it with the right intentions, it can become a digital savior. The speed at which data is uploaded to digital media is unmatchable by humans. Here, AI can act as a filter, identifying and blocking objectionable content, deepfakes, and fake news before they spread. AI can be helpful in implementing the Right to Be Forgotten. What is needed is a policy that compels tech companies to ensure their AI models are security and privacy-friendly. India must develop a robust framework for the Right to Be Forgotten. This should not be merely a paper right; it should be a system where victims can be heard with a single click. We need special digital tribunals where technical experts and legal experts collaborate to make quick decisions. The Data Protection Board should be empowered to impose heavy fines on platforms that do not delete data even after receiving orders. The law must clarify under what circumstances data can be deleted and where public interest is paramount. Another important reform should be to make transparency reports mandatory for tech companies, so that How many requests they accepted and how many they rejected. We must develop a digital culture where we respect the privacy of others. The law will do its work, AI will improve its, but we must understand that every person deserves a second chance. The right to be forgotten in the digital age is an attempt to preserve human dignity. Until we integrate technology and law with human sensibilities, we will remain imprisoned in this digital cage.

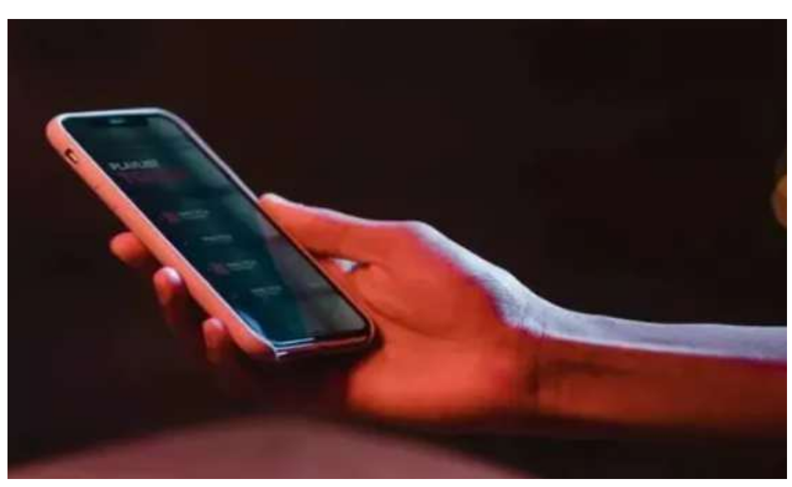

आप मुझे इंसाफ दिला पाएंगे: आपके बड़े अफसरों को गिफ्ट देता है फैक्टरी मालिक, डीआईजी से बोला ठेकेदार

मुरादाबाद में पाकबड़ा क्षेत्र के ठेकेदार ने डीआईजी मुनिराज से शिकायत कर फैक्टरी मालिक पर 56 लाख नहीं देने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि अधिकारियों के नाम पर उसको धमकाया

जाता है। डीआईजी ने प्रार्थना पत्र लेकर मामले की जांच और रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।मुरादाबाद एसएसपी दफ्तर में सोमवार की सुबह निरीक्षण करने पहुंचे डीआईजी मुनिराज जी से पाकबड़ा क्षेत्र में रहने वाला एक ठेकेदार बोला.. फैक्टरी मालिक ने लाखों रुपये का भुगतान रोक रखा है। वह मुरादाबाद में तैनात रह चुके आईपीएस और आईएएस अफसरों के नाम पर धमकता है और कहता है कि सभी को उसकी फैक्टरी से गिफ्ट जाते हैं।डीआईजी ने उसका प्रार्थना पत्र देकर जांच के आदेश दे दिए। पाकबड़ा के लोधीपुर राजपूत निवासी ठेकेदार रणवीर सिंह ने डीआईजी को दिए प्रार्थना में बताया कि 2022 में उन्होंने मार्टको एक्सपोर्ट की दो बाउंड्रीवाल तैयार कराईं थीं जिस पर करीब 95 लाख रुपये खर्च हुए।कंपनी की ओर से अब तक 39 लाख रुपये का भुगतान किया गया जबकि 56 लाख रुपये बकाया हैं। ब्याज सहित करीब 80 लाख रुपये हो चुके हैं। लेकिन हर बार आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। तकादा करने पर कई बार सिक्योरिटी गार्डों से बदसलूकी कराई गई। उन्होंने तीन फरवरी 2026 को हिसाब के बहाने बुलाकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। सोमवार सुबह कलक्ट्रेट पहुंचकर ठेकेदार ने कंपनी मालिक और उनके भाइयों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग की। इस दौरान ठेकेदार ने यह भी बताया कि फैक्टरी के मालिक अधिकारियों के नाम पर धमकाते हैं। कहते हैं कि जिला तो छोड़िए आस पड़ोस के जिलों के अधिकारी भी भी उनकी फैक्टरी से ही सामान लेकर आते हैं। डीआईजी मुनिराज जी ने बताया कि पाकबड़ा क्षेत्र से एक फरियादी मिला था। उसने फैक्टरी मालिक पर भुगतान न करने का आरोप लगाया है। इस मामले में जांच कर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।ठेकेदार द्वारा दिया प्रार्थना पत्र देने का मामला मेरे संज्ञान में है। एसएसपी को बताया गया है और पूरे मामले का हिसाब तैयार कराया जा रहा है। चार साल पहले का पर्चा दिया है ठेकेदार ने। संजीव जैन, मार्टको एक्सपोर्ट के मालिक कलक्ट्रेट में प्रदर्शन, आत्महत्या की धमकी दी – पाकबड़ा के लोधीपुर राजपूत निवासी ठेकेदार रणवीर सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान कंपनी के मजदूर भी ठेकेदार के साथ मौजूद रहे और उन्होंने फैक्टरी के फोटो को अपने हाथों में ले रखा था। ठेकेदार ने धमकी दी कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो वह आत्महत्या कर लेगा। पुलिस कर्मियों ने उसे हटाने का प्रयास किया लेकिन वह प्रदर्शन करते रहे और डीआईजी से मिलने के बाद ही वह शांत हुए। इसके बाद पुलिस उसे पाकबड़ा थाने भेज दिया। जहां थाना प्रभारी और सीओ ने उसकी बात सुनी।

पेनल्टी टैरिफ रिफंड का निर्णय निर्यातकों के लिए नया अवसर

भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका द्वारा 25त्न पेनल्टी टैरिफ वापस करने के फैसले ने निर्यातकों, विशेषकर मुरादाबाद के पीतल व हस्तशिल्प उद्योग को बड़ी राहत दी है। यह रिफंड 27 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 के बीच निर्यात किए गए माल पर लागू होगा। इस निर्णय से अनुमानित ?40,000 करोड़ की राहत भारतीय व्यापार जगत को मिलने की संभावना है, जिसका सीधा ल ा भ और निर्यातकों तक पहुंचेगा। यह कदम न केवल आजीविका को भी मजबूत करेगा। उद्योग जगत को आत्मनिर्भरता आएगी।कैसे मिलेगा लाभ– अमेरिकी निर्यातकों के साथ साझा किया जाएगा। – जिले के गिफ्टिंग उत्पादों की अमेरिकी मांग में वृद्धि की मुरादाबाद के उत्पाद अब अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों प्रवाह में सुधार होगा, जिससे उत्पादन और रोजगार और बेहतर भुगतान मिलने की संभावना– अध्यक्ष, एसोसिएशन नवेद उर रहमान ने बताया कि निर्णय ऐतिहासिक राहत है। पेनल्टी टैरिफ रिफंड व टैरिफ क्षमता कई गुना बढ़ेगी। इससे निर्यात में वृद्धि के मजबूत होगी। मुरादाबाद का उद्योग वैश्विक बाजार करेगा। लघु उद्योग भारती मेरठ संभाग के वाइस

मुरादाबाद के हजारों कारीगरों, यूनिट मालिकों व्यापार को गति देगा, बल्कि कारीगरों की उम्मीद है कि आने वाले महीनों में उद्योगों में आयातकों को मिलने वाला रिफंड भारतीय धातु–हस्तशिल्प, होम डेकोर, किचनवेयर और उम्मीद। – टैरिफ 50त्न से घटकर 18त्न होने से पर उपलब्ध होंगे। – निर्यातकों की नकदी दोनों बढ़ेंगे। – कारीगरों को अधिक ऑर्डर मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स मुरादाबाद के हस्तशिल्प उद्योग के लिए में कमी से निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक साथ हजारों कारीगर परिवारों की आय भी में और अधिक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज प्रेसीडेंट अंशुल अग्रवाल ने बताया कि इससे स्थानीय उत्पादों के निर्यातकों को काफी राहत मिलेगी। आयरन, स्टील और एल्यूमीनियम आदि पर यदि स्पष्टता हो जाए तो जिले का उद्योग काफी आगे बढ़ेगा। जैसे वुड टिंबर लिखा है लेकिन हम आइटम बेचते हैं इस पर हम बच जाएंगे। लेकिन अन्य उत्पादों पर स्पष्टता आने के बाद इंडस्ड्री काफी मजबूत होगी। इसके लिए सरकार का आभार जताते हैं। नेशनल चेयरमैन यस विशाल अग्रवाल ने बताया कि अमेरिका द्वारा पेनल्टी टैरिफ रिफंड होने से बायर्स से अटकी बातचीत फिर से शुरू हो गई है। इससे मुरादाबाद सहित भारत के निर्यात को ऊंचाई मिलेगी। आगामी फेयर में इसका सकारात्मक रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में स्थानीय निर्यातकों व कारोबार से जुड़े लोगों को काफी आसानी हो जाएगी, निर्यात भी बढ़ेगा।

किराए की दरों में रियायत की घोषणा से अब व्यापारियों में विरोधाभास

मुरादाबाद। नगर निगम के 488 दुकानों पर बढ़े किराए की रॉर समाप्त करने के लिए दूसरे दिन सोमवार को भी व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने निगम की दुकानों के किराएदार व्यापारियों के साथ पीलीकोठी स्थित महापौर के शिविर कार्यालय पर पटेल से भी मिले। उनके द्वारा किराए की दरों को 400 रुपये प्रति स्क्वायर वर्ग मीटर प्रति महीना लेने की व्यापारियों ने पहले महापौर विनोद अग्रवाल व अपर निशा मिश्रा के साथ पीलीकोठी स्थित महापौर के 18 प्रतिशत और करने की बात कही। वहीं वीरेंद्र ने नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल से उनके शिविर कार्यालय नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने पहले निगम द्वारा तय प्रति महीना की जगह अप्रैल 2025 से राउंड फीगर में का भरोसा दिया। इसके बाद व्यापारियों की ओर से की सर्वसम्मति से निर्णय लिया। हालांकि कुछ इनकार कर दिया। व्यापारी सुरक्षा फोरम के महामंत्री

बैठक हुई। बाद में कुछ व्यापारी नगर आयुक्त दिव्यांशु किराए की दरों को 434 की जगह राउंड फीगर कर सहमति पर कुछ व्यापारियों ने रजामंदी जताई। नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, संयुक्त नगर आयुक्त शिविर कार्यालय में वार्ता की। इसमें महापौर ने छूट अरोड़ा, पार्षद देशरत्न कत्याल व कई अन्य व्यापारियों में मुलाकात की। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को किए किराए 434 रुपये प्रति स्कवायर वर्गमीटर 400 रुपये प्रति स्कवायर वर्गमीटर प्रति महीना करने अपना विरोध समाप्त करते हुए दुकानों को खोलने पदाधिकारियों व व्यापारियों ने इसे भी मानने से नितिन राज ने कहा कि यह मान्य नहीं है। नगर आयुक्त ने बताया कि बैठक में पहले महापौर ने और उसके बाद उन्होंने रियायत देने की बात कही। किराए की दरों को भी 400 रुपये प्रति स्क्वायर वर्गमीटर प्रति महीने करने का निर्णय लिया। जिसके बाद व्यापारियों ने इस पर सहमति व्यक्त की। पार्षद देशरत्न कत्याल ने कहा कि आम सहमति से जो समझौता हुआ वह व्यापारियों को मान्य है। अधिकांश व्यापारियों ने दुकानें शाम को खोल दी गई।

हर–घर जल योजना की हकीकत: तीन साल बाद भी गोट में टंकी से जलापूर्ति नहीं

हर घर जल–जल जीवन मिशन, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे) व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की योजना जिले में अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है। तीन वर्षों में कई गांवों में टंकी का निर्माण अधूरा है या निर्माण के बाद भी जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। योजना के अंतर्गत जिले की 647 ग्राम पंचायतों में 2024 तक 440 ग्राम पंचायतों में पानी की टंकियों का निर्माण पूरा किया जाना था, लेकिन कई स्थानों पर आज तक जमीन उपलब्ध नहीं हुई, कहीं केवल बोरिंग कर छोड़ दिया गया, तो कई गांवों में टंकियों के बनने के बाद भी पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई।सदर ब्लॉक के गोट गांव में 6 जनवरी 2023 को टंकी का निर्माण शुरू हुआ था। उस समय इससे लाभान्वित होने वाली आबादी 7,990 थी, जो अब बढ़कर लगभग 10,000 हो चुकी है। करीब 281.78 लाख रुपये की लागत से बनी यह पानी की टंकी निर्धारित समय से दो वर्ष बाद भी चालू नहीं हो सकी है। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन जगह–जगह से फट चुकी है। खुदाई से सड़कें भी खराब हो गई हैं, लेकिन अब तक एक बूंद पानी नसीब नहीं हुई। ग्राम पंचायत सचिव सुशील यादव ने बताया कि टंकी निर्माण के दौरान हुई खोदाई से गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि जलापूर्ति अब तक शुरू नहीं हो पाई है। पंचायत सचिव अभिरूप टंडन ने बताया कि चक बेगमपुर और ठीकरी गांवों में पानी की टंकी होने के बावजूद कुछ घंटों के लिए भी नियमित जलापूर्ति नहीं हो पाती।पंचायत सचिव महेंद्र सिंह ने बताया कि लदावली गांव में पानी की टंकी के लिए चिन्हित भूमि पर केवल बोरिंग का गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। पांच प्रतिशत भी टंकियां चालू नहीं– एडीओ पंचायत इरफान मलिक ने बताया कि हर घर जल योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत आती है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन है, जिसमें जल संरक्षण और जल प्रबंधन भी शामिल है। उन्होंने स्वीकार किया कि जिले में पांच प्रतिशत पानी की टंकियां भी पूरी तरह से चालू नहीं हुई हैं।

संक्षिप्त समाचार

संभल हिंसा मामला: पुलिस अफसरों पर एफआईआर के आदेश को चुनौती की याचिका पर सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और एएसपी अनुज चौधरी की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की, जिनमें संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) द्वारा नवंबर, 2024 की हिंसा के संबंध में एएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ के समक्ष हुई। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभान्शु सुधीर ने पिछले महीने घायल युवक के पिता यामीन की अर्जी पर पारित किया गया था। उक्त आदेश पारित होने के लगभग एक सप्ताह बाद संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का तबादला सुल्तानपुर कर दिया गया। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने राज्य की ओर से बताया कि मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया और कानून की सीमाओं का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि धारा 175(4) लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित मामलों में तुच्छ या उत्पीड़न आपराधिक कार्यवाही से बचाने के लिए दो–चरणीय प्रक्रिया अनिवार्य है, जैसे– वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करना, घटना की परिस्थितियों के संबंध में संबंधित लोक सेवक के कथनों पर विचार करना। महाधिवक्ता ने यह भी बताया कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट तो मंगाई गई, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया और आदेश में उसका उल्लेख तक नहीं है।राज्य ने यह भी तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में प्रारंभिक स्तर पर थाने में शिकायत करने का उल्लेख नहीं किया, जबकि यह विधि के तहत अपेक्षित शर्त है, साथ ही पुलिस रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि घटना के संबंध में पहले से मामला दर्ज कर जांच की जा रही है, लेकिन उसे भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया। राज्य की ओर से यह भी रेखांकित किया गया कि बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि यदि आरोप प्रथमदृष्टया निराधार, असंगत या अत्यंत असंभावित हों तो आवेदन खारिज कर सकते हैं। समता भाव के कारण मामले की सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

फिर बिगड़ा मौसम, सुबह धूप के बाद छाए बादल, सप्ताह के अंत तक बारिश के आसार

मुरादाबाद। मौसम हर दिन बदल रहा है। धूप तो कभी कोहरा और बादल छा रहा है। तापमान में असंतुलन के चलते लोग बीमार भी हो रहे हैं।

इन दिनों सरकारी अस्पताल के अलावा निजी क्लीनिकों में भी वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम, सांस फूलने से पीड़ित मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। चिकित्सक इलाज के साथ ही सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहे हैं। सोमवार को सुबह कोहरा रहा, फिर धूप निकला और नौ बजे के करीब अचानक बादलों ने सूर्यदेव को ढक लिया। हवा चलने से गलन और ठंड बढ़ गई।

पूरे दिन कभी बादल तो कभी बादलों की ओट से सूर्यदेव दर्शन देते रहे। इससे ठंड से लोग ठिठुरते भी रहे। मौसम विभाग के अनुसार अभी महाशिवरात्रि तक ठंड यूं ही रहेगी। सुबह कोहरा तो दिन में धूप भी निकल सकती है। कभी बादलों के चलते छिटपुट या हल्की बारिश भी हो सकती है। आर्द्रता बढ़ने से वातावरण में नमी बरकरार रहेगी। दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर होने से भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। सोमवार को अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। अभी मौसम में उतार चढ़ाव का क्रम जारी रहने का अनुमान जताई गई है।

बदलाव व तापमान में असंतुलन से हो रही बीमारी– बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. रवि गंगल ने बताया कि इन दिनों मौसम में लगातार बदलाव व तापमान में असंतुलन से बच्चे और बड़े बीमार पड़ रहे हैं। इन दिनों वायरल फीवर, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, सीने में दर्द, सांस फूलने, बहुत छोटे बच्चों में पसली तेज चलने की समस्या अधिक हो रही है। ऐसे में बच्चों के अभिभावकों को चाहिए कि वह उन्हें ठंडे वातावरण में काफी बचाकर रखें। आइसक्रीम, फ्रिज का पानी न पीने दें। बासी भोजन से भी परहेज करें। सुपाच्य और ताजा भोजन दें। घरों में रहने के दौरान और बाहर निकलते समय पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें। रात में सुबह निकलते विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए–11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद–244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी, डबलफाटक जनपद–मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक – नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991

RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

दस हजार युवाओं को रोजगार देने की तैयारी, 15 हजार करोड़ औद्योगिक निवेश का लक्ष्य

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली। जिले को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने के साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जीबीसी - 5 में जनपद को 15 हजार करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश बढ़ाने का लक्ष्य मिला है। इसे धरातल पर उतारने के लिए उद्योग विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इतने बड़े निवेश से जिले के दस हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए उद्यमियों के साथ विभाग ने बैठक भी करना शुरू कर दिया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी-5) के तहत जिले में एक बार फिर से उद्योग स्थापना की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत जिले को 15 हजार करोड़ का लक्ष्य मिला है। इसे पूरा करने के लिए 21 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उद्योग विभाग की मानें तो अब तक करीब ढाई हजार करोड़ रुपये निवेश के करार भी हो चुके हैं। करीब ढाई हजार करोड़ के निवेश की प्रक्रिया चल रही है। उद्यमियों से संपर्क कर निवेश और उसके लाभ बताए जा रहे हैं। जबकि, जीबीसी 4.0 में 30 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य मिला था। इसके सापेक्ष 318 उद्योगों के लिए 35,101 करोड़ रुपये के निवेश करार हुए थे। जीबीसी-5 के लिए बरेली विकास प्राधिकरण और यूपीसीडा को चार-चार हजार करोड़ रुपये के निवेश करार का लक्ष्य मिला है। उपायुक्त उद्योग विकास यादव ने बताया कि शासन से 15 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य मिला है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अलग-अलग विभागों को लक्ष्य दिए गए हैं। करीब ढाई हजार करोड़ रुपये के निवेश करार हो चुके हैं। लक्ष्य हासिल करने के लिए निवेशकों से संपर्क कर उनके साथ बैठक भी की जा रहा है। इन निवेश प्रस्तावों के आकार लेते ही युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता साफ हो जाएगा।

चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चे ने किया आत्महत्या का प्रयास

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली । चाइल्ड केयर सेंटर मैं मौजूद एक बच्चे ने केंद्र के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया लेकिन केयरटेकर ने उसे बचा दिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया बारादरी थाना क्षेत्र के हरुनगला निवासी विजेंद्र के 14 वर्षीय बेटे अजय को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया बताया जाता है कि अजय शनिवार को अपने घर से बाहर गया था और वापस नहीं लौटा वह मूल रूप से शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के गांव भुंडपुर का रहने वाला है उसके पिता सेना में तैनात है और इन दोनों अवकाश पर घर आए हुए हैं शनिवार को अजय अचानक घर से बाहर गया और वापस नहीं लौटा जिसकी जानकारी पुलिस को भी दे दी गई तब चाइल्ड केयर की टीम में उसे बरामद करते हुए उसे पटेल चौक के पास चाइल्ड केयर सेंटर भेज दिया जहां पर आज वह शौच के लिए जाने की बात कहकर एक कमरे में गया और वहां पर तार से खुद को फांसी लगाने का प्रयास किया लेकिन वहां मौजूद केयरटेकर अभिषेक में उसे देख लिया और बचा लिया घटना की जानकारी अभिषेक ने केंद्र के आला अधिकारियों को दी और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया जहां से उसके घर वालों को सूचना देने के बाद निजी अस्पताल भेजा गया उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है अजय कक्षा 6 का छात्र बताया जाता है वही बच्चे के पिता ने बताया कि बच्चे ने घर पर ही आत्महत्या का प्रयास किया है मामले की जांच जारी है

यातायात पुलिस ने पोस्टर जारी कर आमजन को किया जागरूक

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली । ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर आम जनता को जागरूक किया है। पोस्टर के माध्यम से जनता को बताया कि सड़क पर नियमों का पालन करना केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। पुलिस अधीक्षक मोहमद अकमल खां का कहना है कि शहर में बढ़ते वाहन दबाव के बीच नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हो गया है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना, रेड लाइट पर रुकना और गलत दिशा में वाहन न चलाना जैसे नियमों से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। ट्रैफिक विभाग ने विशेष रूप से युवाओं से अपील की है कि वे स्टंटबाजी, तेज रफ्तार और मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाने से बचें। पुलिस का कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही गंभीर हादसों का कारण बन सकती है। इसके साथ ही बरेली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि नागरिकों की सहायता के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन हर समय सक्रिय है। किसी भी आपात स्थिति, दुर्घटना या यातायात समस्या के दौरान हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकती है। शहर में सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा चौराहों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। यातायात पुलिस का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक कर दुर्घटनाओं को रोकना है। बरेली क़े नागरिकों से अपील की कि वे जिम्मेदार नागरिक बनें और नियमों का पालन कर बरेली को एक सुरक्षित और अनुशासित शहर बनाने में पुलिस का सहयोग करें।

100 करोड़ से संवारा जा रहा है विश्व विद्यालय परिसर

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के तहत मिले 100 करोड़ रुपये के अनुदान से विश्वविद्यालय के विकास को नई गति दी जा रही है। मौजूदा वर्ष संस्थान के लिए परिवर्तनकारी माना जा रहा है। इसमें आधुनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल शिक्षण व्यवस्था और वैश्विक स्तर की सुविधाओं के निर्माण पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इससे विश्वविद्यालय न केवल तकनीकी रूप से मजबूत होगा, बल्कि छात्रों, शोधार्थियों और नौकरीपेशा युवाओं के लिए भी गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा के नए रास्ते खुलेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुदान में मिली धनराशि से तीन बड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। इन्हें इस वर्ष धरातल पर उतारने की योजना है। इनमें डिजिटल लर्निंग हब, इन्क्यूबेशन पायलट फैसिलिटी और अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट छात्रावास शामिल हैं। इन परियोजनाओं के जरिये शिक्षा के साथ-साथ शोध, नवाचार और वैश्विक सहयोग को भी मजबूती मिलेगी। सबसे प्रमुख परियोजना डिजिटल लर्निंग हब होगी, जो ई-कंटेंट निर्माण, ऑनलाइन कोर्सेज और हाइब्रिड लर्निंग के लिए वन-स्टॉप सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। यूजीसी से 11 नए पाठ्यक्रमों को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। इससे छात्रों को आधुनिक विषयों पर पढ़ाई का अवसर मिलेगा। शिक्षक भी ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को पढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और इंटरएक्टिव बनेगी। मीडिया प्रभारी रुहेलखंड विश्वविद्यालय डॉ. विनय वर्मा ने बताया कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर निरंतर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2026 में इंटरनेशनल ट्रांजिट छात्रावास, डिजिटल लर्निंग हब और इन्क्यूबेशन पायलट फैसिलिटी का निर्माण किया जा रहा। इसकी नई सुविधाओं में आधुनिक तकनीक, लर्निंग आदि के माध्यम विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

महाशिवरात्रि व आगामी त्यौहारों को सकुशल और सौहार्दपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु हुई बैठक

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली । अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे की अध्यक्षता में महाशिवरात्रि आगामी त्यौहारों पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में पीस कमेटी की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में आगामी त्यौहारों को लेकर क्षेत्रवार लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गयी और सम्बंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए गए। बैठक में आयोजकों द्वारा शोभायात्रा के दौरान लाईट आपूर्ति सुचारू रखने, मांस-मदिरा की दुकानें शोभायात्रा के दौरान बंद कराने, आवासीय क्षेत्र की पतली गलियों में लटकी विद्युत केबिल को सही कराने आदि के बारे में अनुरोध किया गया। धोपेश्वर नाथ मंदिर के महंत द्वारा जानकारी दी गयी कि मंदिर प्रांगण में निर्माण कार्य पर्यटन विभाग के अन्तर्गत संचालित है, जिस कारण निर्माण सामग्री फैली हुई है, जिससे महाशिवरात्रि पर आने वाले भक्तगणों को असुविधा हो सकती है। उक्त सभी समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बंधित विभागों के अधिकारियों निर्देशित किया गया। बैठक में निर्देश दिए गए कि सातों प्रमुख शिव मंदिरों पर एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड की गड़ियां की व्यवस्था तथा जलकुंड वाले मंदिरों में गोताखोरों की तैनाती आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शोभायात्रा के आयोजकों को भी निर्देश दिए गए कि शोभायात्रा में जो गाड़ियां लगायी जाएं उनकी फिटनेस भी चेक करा ली जाए, जिससे वे बीच यात्रा में खराब ना हो तथा शोभायात्रा निकलने के समय का विशेष ध्यान दिया जाए, शोभायात्रा का जो समय सम्बंधित थाने को नोट कराया जाए उसी समय पर निकाली जाएं। शोभायात्रा के दौरान डीजे आदि के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया जाए तथा डीजे पर महौल खराब करने वाले गाने ना बजाए जाएं। बैठक में निर्देश दिए गए कि मंदिर में प्रवेश व निकास द्वार अलग-अलग बनाए जाएं, मंदिर का फर्श फिसलन भरा ना हो इस बात का ध्यान रखा जाए, मंदिर प्रांगण में विद्युत तार खुले में ना रहें और मंदिर प्रांगण को साफ-सुथरा रखा जाए तथा मंदिर के जो सीसीटीवी कैमरे खराब हो उन्हें समय रहते ठीक करा लिया जाएं। बैठक में निर्देश दिए गए कि महाशिवरात्रि के पर्व पर बड़े झूले बिना अनुमति के ना लगाए जाएं और सुरक्षा व्यवस्था की विशेष ध्यान रखा जाए तथा झूले का मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल सार्टिफिकेट अवश्य लिया जाए। पार्किंग स्थान सुनिश्चित कर लें। निर्देश दिए गए कि शोभायात्रा के रुटों का पहले से भ्रमण कर देख लें कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। बैठक में निर्देश दिए गए कि थानावार पीस कमेटी की बैठक अवश्य कर ली जाए तथा पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी जाएं। आयोजकों के पास अपने क्षेत्र के पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों के नम्बर होने चाहिए, जिससे असुविधा की स्थिति में सम्पर्क किया जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 विश्राम सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक, पुलिस अधीक्षक नार्थ, पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक क्राइम, सीओ एलआईयू, उपजिलाधिकारी सदर, नवाबगंज, फरीदपुर, मीरगंज, बहेड़ी सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

श्री हनुमान चालीसा में जय हनुमान के उदघोष से गूंजा श्री हरि मंदिर

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली। श्री हरि मंदिर मॉडल टाऊन बरेली में मंगलवार को भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिली । सुबह के सत्र में मंदिर के पंडित सुनील शास्त्री के द्वारा श्री हनुमान जी का विधिवत पूजन व श्रृंगार किया गया। भक्तजनों द्वारा मंगलवार को अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु पधारते है और श्री हनुमान जी की पूजा करते है । शाम के सत्र में मंदिर अध्यक्ष सुशील अरोड़ा ने ज्योत प्रवाजलित की और श्री हरि संकीर्तन श्री हरि संकीर्तन मंडल द्वारा भजनों की रसधारा बहाई गई जिस मे रवि छाबड़ा ने है दुःख भंजन मारुति नंदन.........,संजय आनन्द ने मंगल मूर्ति राम। लारे..........,पंकज नेआज मंगलवार है ....,सचिन सेठी ने कीजे केसरी के लाल ....और भाई सौरभ ने राम भी मिलेगे तुझे श्याम भी मिलेगे.........जतिन दुआ ने झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमान ....आदि आदि भजनों से सारा श्री हरि मंदिर प्रांगण भक्तिमय हो गया। उसके बाद सभी उपस्थित भक्तजनों द्वारा सामूहिक श्री हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और श्री हनुमान जी की सामूहिक आरती हुई, व शयन आरती के पाश्चात्य सभी भक्तजनों में भंडारा प्रसादी का वितरण हुआ। मंदिर सचिव रवि छाबड़ा ने बताया कि सामूहिक श्री हनुमान चालीसा व आरती विगत कई वर्षो से श्री हरि मंदिर प्रांगण में हो रही है,जिस में सभी आयु वर्ग में लोग सम्मिलित होते है, विशेष कर युवाओं का जागरूक होना विशेष है। आज के कार्यकम में मंदिर अध्यक्ष सुशील अरोरा,सचिव रवि छाबड़ा, उपाध्यक्ष अश्विनी ओबेरॉय,संजय आनन्द,गोविंद तनेजा,रंजन कुमार,हरीश लुनियाल, राजेश अरोरा,गिरीश आनन्द,वा अन्य सदस्य उपस्थित रहे। महिला मंडल अध्यक्ष रेनू छाबड़ा भी अपनी टीम के साथ शामिल रही। युवा सदस्यों ने प्रसाद वितरण की सेवा की। समापन पर मंदिर सचिव रवि छाबड़ा ने सभी भक्तजनों का आभार व्यक्त किया और सभी भक्तजनों को भंडारा प्रसाद वितरण किया गया।

प्रिय सुधि पाठको आप अपना यहाँ शुभकामना सन्देश (Birthday, anniversary, any kind of message) कम कीमत में विज्ञापन छपवाए - 9027776991

संक्षिप्त समाचार

बेटियों के एडमिशन में पांच फीसदी से ज्यादा उछाल

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जैसी योजनाओं का प्रदेश में बड़ा असर नजर आ रहा है। यू डाइस प्लस पोर्टल के ताजे आंकड़ों को देखा जाए तो बीते चार वर्षों में प्रदेश में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या करीब 12 लाख (5.1 प्रतिशत) बढ़ गई है। बरेली जिले की बात की जाए तो यहां बीते चार वर्षों में बेटियों का नामांकन लगभग 10 फीसदी बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (जन्म से स्नातक तक 25,000 रुपये की सहायता), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं (प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक) प्रमुखता से चल रही हैं।

30 साल के लिए वैग्माइन को मिला अर्बन हाट का ठेका

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित अर्बन हाट एंड हैंडीक्राफ्ट सेंटर के संचालन को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला गया है। विकास भवन के पास 46,135 वर्ग मीटर की जमीन पर 157.67 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस बहुउद्देश्यीय हाट का ठेका 30 साल के लिए बेंगलुरु की वैग्माइन इंटरप्राइजेज कंपनी को सौंपा है। एजेंसी ने सोमवार को इसकी रजिस्ट्री पूरी कर ली है। इस दौरान 59.70 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 2.38 करोड़ के ई-स्टांप शुल्क जमा किए। रजिस्ट्रेशन फीस और ई-स्टांप शुल्क का भुगतान के बाद संचालन का रास्ता साफ हो गया है। अर्बन हाट एंड हैंडीक्राफ्ट सेंटर को शहर के लिए एक प्रमुख व्यावसायिक, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। निर्माण कार्य का ठेका 7 सितंबर 2021 को मैसर्स आरपीपी इंफ्रा को दिया गया था। करीब ढाई साल की मेहनत के बाद 30 दिसंबर 2023 को सेंटर पूरी तरह तैयार हो गया। सोमवार को रजिस्ट्री समेत सभी प्रक्रियाएं पूरी होने पर हाट के सारे अधिकार और संचालन सीधे वैग्माइन इंटरप्राइजेज के नियंत्रण में आ गए। सीईओ बरेली स्मार्ट सिटी कंपनी संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि अर्बन हाट परियोजना शहर के विकास और स्थानीय कारीगरों के लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वैसे तो कंपनी को ठेका पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन सोमवार को वैग्माइन इंटरप्राइजेज ने कानूनी रूप से रजिस्ट्री कर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है।

होटलों-रेस्टोरेंट में मिलावटी सरसों तेल खपाए जाने की आशंका, कमिश्नर ने दिए जांच के निर्देश

क्यूँ न लिखूँ सच/ पं सत्यमशर्मा / बरेली। जनपद में भारी मात्रा में मिलावटी तेल के तैयार होने की शिकायतों और छापेमारी के बाद आशंका जाहिर की जा रही है कि मिलावटी तेल का इस्तेमाल होटलों और रेस्टोरेंट में खपाया जा रहा है। इस पर कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी ने होटलों व रेस्टोरेंटों में सघन जांच करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर के निर्देश पर एफएसडीए की तीन सदस्यीय टीम गठित की गयी है। यह टीम कई दिनों तक छापेमारी कर कई बिंदुओं पर जांच करेगी। इसमें होटलों-रेस्टोरेंट में सरसों के तेल की खपत और कहां-कहां से माल मंगाया जा रहा है, यह भी जांचा जाएगा। कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त खाद्य सहित अन्य अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त कार्यालय में बैठक की। तेल में मिलावट की आशंका पर हो रही छापेमारी के संबंध में जानकारी की। बैठक में आशंका जाहिर की गई कि मिलावटी तेल का इस्तेमाल होटलों और रेस्टोरेंट में किया जा रहा है। इस पर कमिश्नर ने सहायक आयुक्त खाद्य को होटलों और रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की सघन जांच कराने के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए।

क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से निजात पाने और स्थायी समाधान के रूप में तटबंध (Embankment) निर्माण की मांग

क्यूँ न लिखूँ सच/ श्याम जी कश्यप / फर्रुखाबाद 7 क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से निजात पाने और स्थायी समाधान के रूप में तटबंध (Embankment) निर्माण की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। %तटबंध बनाओ जन संघर्ष समिति% के तत्वाधान चेतना पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह तक जाएगी। यात्रा का मार्ग और कार्यक्रम- समिति निम्नलिखित रूप से निर्धारित किया गया है: प्रारंभ: प्रथम दिन का पड़ाव: यात्रा सरी सवासी, खुटिया, भरका पहुंचेगी, जहाँ रात्रि विश्राम किया जाएगा। तारापुर, चाचूपुर, जमापुर, गोटिया, इमादपुर, रामपुर को भेजा जाएगा ज्ञापन- पदयात्रा के दौरान जनहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन समिति का मुख्य उद्देश्य प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समिति के अध्यक्ष भईयन मिश्रा ने बताया कि इस उत्साह है। यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोमल पांडे: विभाग अध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल

में आगामी 11 फरवरी से एक विशाल पांच दिवसीय %जन यात्रा फर्रुखाबाद के कढ़हर से शुरू होकर बदायूं के अतेना घाट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पदयात्रा का कार्यक्रम 11 फरवरी (बुधवार), सुबह 11:00 बजे, स्थान- कढ़हर। बारा खेड़ा अंतर, अर्जुनपुर, ज्ञानपुर और सलेमपुर होते हुए द्वितीय दिन (12 फरवरी): यात्रा भरका से आगे बढ़कर और जोगराजपुर होते हुए अलीगढ़ तिराहे पहुंचेगी। मुख्यमंत्री की इस मांग को सरकार तक पहुँचाने के लिए उत्तर प्रदेश के उप जिलाधिकारी (स्ष्ठरू) अमृतपुर को सौंपा जाएगा। संघर्ष समस्या की ओर आकर्षित करना है। जनसंपर्क और उत्साह- यात्रा को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और क्षेत्रीय लोगों में भारी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सहयोगी: राजीव प्रताप सिंह: अधिवक्ता, हाईकोर्ट इसके साथ ही नितेश मिश्रा, अनूप प्रधान, अनमोल अग्निहोत्री और विभिन्न ग्राम प्रधान (दारापुर, बहादुरपुर, बदनपुर) लोगों को इस यात्रा से जोड़ने के लिए निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं। संक्षिप्त नोट: यह पदयात्रा क्षेत्र के किसानों और निवासियों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बने तटबंध निर्माण को अमली जामा पहनाने के लिए एक महत्वपूर्ण जन-आंदोलन के रूप में देखी जा रही है।

27 वर्षीय युवक का शव घर के बाहर पेड़ से लटका हुआ पाया गया

क्यूँ न लिखूँ सच/ श्याम जी कश्यप /जनपद के अमृतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिथनापुर गांव में उस

वक्त सनसनी फैल गई, जब एक 27 वर्षीय युवक का शव घर के बाहर पेड़ से लटका हुआ पाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक की पैंट पर %आई लव यू% के साथ एक महिला का नाम लिखा हुआ था, जिससे मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। मजदूरी करता था युवक- मृतक की पहचान संदीप सिंह (27 वर्ष) के रूप में हुई है। संदीप मूल रूप से कासगंज जिले के गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र के लालूपुर गांव का निवासी था और वहां अपनी रिश्तेदारी में रहकर मजदूरी का काम करता था। पिथनापुर में उसकी माँ गायत्री देवी, भाई कुलदीप और बहनें रहती हैं। परिजनों को नहीं थी घर आने की खबर- संदीप की माँ ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि संदीप गांव वापस आया है। रविवार सुबह जब वह घर के बाहर निकलीं, तब उन्होंने बेटे का शव नीम के पेड़ से लटका देखा। घटनास्थल के पास एक चारपाई पर संदीप का बैग रखा मिला और उसी चारपाई की रस्सी कटी हुई थी, जिसका इस्तेमाल फंदा बनाने के लिए किया गया। पुलिस कार्रवाई और जांच- सूचना मिलते ही अमृतपुर थाना पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में मामला खुदकुशी का लग रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। ष्टष्ठक्र की जांच: पुलिस ने मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (ष्टष्ठक्र) मंगवाई है ताकि अंतिम समय में हुई बातचीत का पता चल सके। अंतिम संस्कार: सोमवार सुबह कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए पांचाल घाट लेकर रवाना हुए। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सामाजिक न्याय और अधिकारों की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का बड़ा प्रदर्शन

क्यूँ न लिखूँ सच/ श्याम जी कश्यप /फतेहगढ़ फर्रुखाबाद. के फतेहगढ़ सामाजिक न्याय और अधिकारों की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। भारी संख्या में जुटे अधिवक्ताओं ने 'UGC बिल 2026 को लागू करने के समर्थन में कचहरी से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और अपनी मांगों को लेकर बुलंद आवाज उठाई। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन-पैदल मार्च के बाद अधिवक्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहाँ उन्होंने

सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सहित सामाजिक रूप से वंचित नागरिकों के हितों के संरक्षण की मांग की गई है। प्रमुख मांगें और सामाजिक प्रतिनिधित्व- प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के जरिए सरकार से निम्नलिखित मांगें की हैं: संवैधानिक प्रक्रिया: यूजीसी के वर्तमान विनियमों को सुप्रीम कोर्ट की ख्याओं के अनुसार संसद में विधिवत पारित किया जाए। स्टे हटाने की कार्रवाई: इस प्रक्रिया पर लगे कानूनी स्टे को हटाने के लिए सरकार त्वरित कदम उठाए। समता समिति में भागीदारी: प्रस्तावित %समता समिति में सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए 1 सदस्य ST, 2 सदस्य स्ष्ट और 4 सदस्य OBC वर्ग से नियुक्त किए जाएं। निगरानी समिति: निगरानी समिति में भी इसी प्रकार का सामाजिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य करने की मांग की गई है। विचारधारा पर प्रहार प्रदर्शन के दौरान एक अधिवक्ता ने वर्तमान व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज भी कहीं न कहीं मनुस्मृति की विचारधारा हावी है, जिसे बदलने और संवैधानिक बराबरी लाने के लिए इस बिल का पास होना अनिवार्य है। इस मार्च का आयोजन 'ST/SC/OBC साझा समाज के बैनर तले किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय वकील और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। त्नष्ट बिल पर आपकी क्या रॉय है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके अपनी रॉय अवश्य बताएं।

संक्षिप्त समाचार

मां, भगवान मुझे बुला रहे हैं- शिव मूर्ति के सामने युवक ने चाकू से काटी हाथ और गले की नस, तड़प-तड़पकर गई जान

राहुल (30) साकीपुर गांव में किराये के मकान में मां के साथ रहता था। युवक का बुलंदशहर निवासी एक महिला से 2018 में विवाह हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद पत्नी अलग रह रही थी। करीब आठ साल से पत्नी पारिवारिक कारण से अलग बुलंदशहर में रह रही है। उसने युवक पर केस भी कर रखा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा सेक्टर डेल्टा-2 श्मशान घाट में भगवान शंकर जी की प्रतिमा के पास सोमवार एक ऑटो चालक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची सूरजपुर कोतवाली पुलिस का कहना है कि ऑटो चालक ने सब्जी काटने वाले चाकू से हाथ और गले की नस काटकर जान दी है। युवक की पेंट की जेब से गांजा मिला है। युवक पत्नी के अलग रहने के साथ तीन दिन पहले ऑटो छीने जाने की बात से परेशान था। परिजन ने मामले में कोई शिकायत नहीं की है।आठ से पत्नी रह रही थी अलग- जानकारी के अनुसार राहुल (30) साकीपुर गांव में किराये के मकान में मां के साथ रहता था। युवक का बुलंदशहर निवासी एक महिला से 2018 में विवाह हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद पत्नी अलग रह रही थी। करीब आठ साल से पत्नी पारिवारिक कारण से अलग बुलंदशहर में रह रही है। उसने युवक पर केस भी कर रखा है। युवक शराब और गांजे की लत का आदि था। शादी के बाद पत्नी के अलग रहने से वह परेशान था। तीन दिन पूर्व उसकी मां ने काम नहीं करने पर किसी दूसरे युवक को टेंपो चलाने के लिए दे दिया था। इसके बाद से वह मानसिक तनाव में आ गया था। मां से कहता था कि भगवान उसे बुला रहे है।गले पर था कट का निशान, हाथ पर लगा था खून-सोमवार को घर नहीं आने पर परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पुलिस को पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि डेल्टा-2 श्मशान घाट में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। जांच के दौरान मृतक की पहचान राहुल के रूप में हुई। युवक का शव श्मशान घाट में स्थित शंकर जी की मूर्ति के पास मिला। मौके पर शव की स्थिति देखने पर मृतक के गले पर कटा हुआ निशान पाया गया। जबकि उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। घटनास्थल की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए। घटना स्थल के पास सब्जी काटने का चाकू बरामद हुआ है। पारिवारिक समस्याओं के कारण भी काफी तनाव में था- पुलिस को मृतक के परिजनों से जानकारी मिली कि राहुल पिछले कुछ समय से पारिवारिक समस्याओं के कारण काफी तनाव में था। घटना के वक्त उसके पास फोन नहीं था। पत्नी के अलग रहने से युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। आत्महत्या की है।

भीषण सड़क हादसे में 16 वर्षीय हाईस्कूल के छात्र की गई जान

क्यूँ न लिखूँ सच/ श्याम जी कश्यप /फरूखाबाद भीषण सड़क हादसे में 16 वर्षीय हाईस्कूल के छात्र की जान चली गई। घटना इटावा-बरेली हाईवे (ह॥730ष्ट) पर थाना कादरीगेट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अर्जुन नगला गाँव के पास हुई। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्र के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। कोचिंग से घर लौट रहा था मृतक- मृतक की पहचान टिकुरियन नगला निवासी सत्यम पुत्र प्रेम सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, सत्यम आवास विकास स्थित %नेम्स क्लासेस% से कोचिंग पढ़कर लौट रहा था। दोपहर करीब 2 के पास पहुँचा, तभी बेवर की अनियंत्रित और तेज रफ्तार मार दी। अस्पताल में हंगामा बुरा हाल- हादसे के तुरंत बाद एक निजी पिकअप वाहन में (लोहिया) लेकर पहुँचे। तैनात डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी मृत घोषित कर दिया। सत्यम परिजनों में कोहराम मच गया। में शव को मोर्चरी ले जाने से हंगामा किया। उनकी मांग थी चालक की गिरफ्तारी नहीं नहीं कराया जाएगा। सूचना पुलिस भारी बल के साथ समझा-बुझाकर शांत कराया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

अपनी बाइक से घर वापस बजे, जब वह अर्जुन नगला ओर से आ रहे एक डंपर ने उसे पीछे से टक्कर और परिजनों का रो-रोकर परिजन घायल सत्यम को लिटाकर जिला अस्पताल हालांकि, इमरजेंसी ड्यूटी पर ने प्राथमिक जांच के बाद उसे की मौत की खबर सुनते ही गुस्साए परिजनों ने शुरुआत रोक दिया और अस्पताल में कि जब तक आरोपी डंपर होती, तब तक पोस्टमार्टम मिलते ही थाना कादरीगेट पहुँची और परिजनों को जिसके बाद शव को परिवार का बड़ा बेटा था सत्यम- सत्यम अपने तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और इस वर्ष हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा देने वाला था। उसकी मौत से माँ बिनीता देवी और छोटे भाइयों (सुरजीत व सूर्यांश) का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गाँव में इस घटना के बाद शोक की लहर है। हाईवे के डिजाइन पर उठे सवाल- स्थानीय निवासी और प्रत्यक्षदर्शी महावीर सिंह राजपूत ने बताया कि इटावा-बरेली हाईवे पर उचित %कट% न होने के कारण यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द सुधार किया जाए ताकि मासूमों की जान बचाई जा सके। पुलिस की कार्रवाई- थाना कादरीगेट प्रभारी कपिल चौधरी ने बताया कि आईटीआई चौकी प्रभारी विशेष कुमार को पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर भेजा गया है। उन्होंने कहा, पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि फरार डंपर और उसके चालक की पहचान की जा सके। परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन्स मुरादाबाद का वार्षिक निरीक्षण किया गया

क्यूँ न लिखूँ सच/ मुरादाबाद। जनपद मुरादाबाद में दिनांक 10-02-2026 को पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद व अन्य राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाईन्स, जनपद मुरादाबाद में परेड का निरीक्षण व रिजर्व पुलिस लाईन्स की विभिन्न शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा प्रातः पुलिस लाइन्स मुरादाबाद पहुंचकर परेड की गुणवत्ता, अनुशासन एवं टर्नआउट का अवलोकन किया गया । इसके उपरान्त रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित क्वार्टर गार्द, मैस, कैन्टीन, कार्यालय, परिसर आदि का निरीक्षण करते हुए संबंधित व्यवस्थाओं

का जायजा लिया गया । निरीक्षण के क्रम में विशेष जांच प्रकोष्ठ, डीसीआरबी एवं फील्ड यूनिट का निरीक्षण कर अभिलेखों एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित इकाई महिला हेल्प डेस्क, परामर्श केन्द्र, महिला सहायता प्रकोष्ठ, महिला सम्मान कोष, मानवाधिकार आयोग प्रकोष्ठ एवं महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (मिशन शक्ति) का निरीक्षण किया गया तथा महिला एवं बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान पुलिस पेंशनर्स के साथ गोष्ठी आयोजित कर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उनके निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके उपरान्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं, महिला अपराधों एवं जनसुनवाई की समीक्षा की गई तथा कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों के साथ भी गोष्ठी कर स्थानीय समस्याओं, जनसुरक्षा एवं पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। मीडिया बन्धुओं से संवाद के दौरान पुलिस की कार्यवाहियों, कानून-व्यवस्था की स्थिति एवं जनहितकारी प्रयासों की जानकारी साझा की गई । निरीक्षण के अंत में पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय द्वारा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन एवं आमजन के प्रति संवेदनशील रहते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गए। उक्त निरीक्षण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नगर/यातायात, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कांठ व अन्य राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे ।

दैनिक क्यूँ न लिखूँ सच | OWN STATE | www.knlslive.com | 11 February 2026

जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा: संजय यादव बने जिला उपाध्यक्ष, दानी पाण्डेय अंशु पाण्डेय शिवबालक यादव सचिव को मिली जिला सचिव की जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज की सहमति से सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शशी सिंह द्वारा नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा के साथ ही जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। घोषित सूची में सबसे पहले संजय यादव को जिला उपाध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी में उनकी सक्रियता, संगठनात्मक अनुभव और जमीनी पकड़ को देखते हुए नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि उनके नेतृत्व में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। ओडगी क्षेत्र से दानी पाण्डेय को जिला सचिव बनाया गया है। लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रहे दानी पाण्डेय को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर है। उनके साथ अंशु पाण्डेय को भी जिला सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। शिवबालक यादव को संगठन में अहम दायित्व सौंपा गया है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन और मजबूती दोनों सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

इसके अतिरिक्त राजेंद्र यादव को जिला संयुक्त महामंत्री तथा राम कुमार बंछोर को महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। नई कार्यकारिणी में विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने प्रदेश एवं जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने, पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने तथा आगामी चुनावी रणनीतियों को सफल बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नियुक्तियां संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखकर की गई हैं। इससे कांग्रेस संगठन को जिले में नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। जिले भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को बधाई देते हुए नई टीम के साथ मिलकर संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने का संकल्प लिया

सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच बोर्ड परीक्षाएं शुरू

क्यूँ न लिखूँ सच/ राजकुमार शर्मा(कटारे)/ शिवपुरी/पिछोर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं का शुभारंभ मंगलवार 10 फरवरी से अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र के साथ हुआ। परीक्षाओं को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एसडीओपी पिछोर श्री प्रशांत शर्मा, एसडीएम पिछोर श्रीमती ममता शाक्य, जिला शिक्षा अधिकारी श्री विवेक श्रीवास्तव एवं थाना प्रभारी पिछोर श्रीमती नीतू सिंह ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने केंद्रों पर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पिछोर विकासखंड में हायर सेकेंडरी के 9 एवं हाई स्कूल के 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हायर सेकेंडरी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में कुल 1643 पंजीकृत छात्रों में से 1611 छात्र उपस्थित रहे, जबकि 32 छात्र अनुपस्थित पाए गए। परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और कहीं से भी किसी प्रकार की अव्यवस्था या अनुचित गतिविधि की सूचना नहीं मिली। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हायर सेकेंडरी परीक्षाएं 10 फरवरी से 7 मार्च तक एवं हाई स्कूल की परीक्षाएं 17 फरवरी से 6 मार्च तक एक ही पारी में प्रात: 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

संक्षिप्त समाचार

अवैध बोल्डर परिवहन पर प्रशासन की कार्रवाई, ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

क्यूँ न लिखूँ सच/ राजकुमार शर्मा(कटारे)/ शिवपुरी। बैराड़ तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध बोल्डर परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की है। यह कार्रवाई मंगलवार दोपहर लगभग 2=30 बजे की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार श्री अजय परसेडिया को क्षेत्र भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि टोडा के पास पोहरी-मोहना रोड पर अवैध रूप से बोल्डरों का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई और ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया। जब्त वाहन को बैराड़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रकरण तैयार किया जा रहा है, जिसे आगामी कार्यवाही हेतु कलेक्टर कार्यालय भेजा जाएगा। वहां नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी इस प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस का अल्टीमेटम, दी सख्त चेतावनी ।

क्यूँ न लिखूँ सच/ श्याम जी कश्यप /नवाबगंज= नवाबगंज। नगर के मुख्य चौराहे और बाजार क्षेत्र में लगने वाले भीषण जाम से अब आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे दुकानदारों और राहगीरों की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जाम की समस्या से जनता त्रस्त। नवाबगंज के मुख्य बाजार और चौराहों पर आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। इसका मुख्य कारण सड़क किनारे और फुटपाथ पर बढ़ता अतिक्रमण है। ई-रिक्शा, टेम्पो और रेहड़ी-पटरी वालों द्वारा फुटपाथ पर अवैध रूप से कब्जा जमाने के कारण सड़क संकरी हो गई है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। थाना प्रभारी ने जारी की चेतावनी। सोमवार को थाना प्रभारी राजीव कुमार ने मौके का मुआयना किया और स्थिति को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए। पुलिस ने नगर में लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी (अनाउंसमेंट) करवाई और सभी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी। कार्रवाई के निर्देश थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि= सभी दुकानदार, ई-रिक्शा और टेम्पो चालक एक दिन के भीतर फुटपाथ खाली कर दें। रेहड़ी-पटरी वाले भी निर्धारित स्थान के बाहर कब्जा न करें। समय सीमा समाप्त होने के बाद यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो पुलिस द्वारा चालान काटने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता है। किसी को भी फुटपाथ बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्धारित समय के बाद कड़ा रुख अपनाया जाएगा।卐 राजीव कुमार, थाना प्रभारी

(एल्बेंडाजोल) खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई

क्यूँ न लिखूँ सच/ श्याम जी / फर्रुखाबाद 7 उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज ब्लॉक से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहाँ एक विद्यालय में सरकारी अभियान के तहत पेट के कीड़े मारने की दवा (एल्बेंडाजोल) खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और लगभग 20 से ज्यादा बच्चों को आनन-फानन में अस्पताल पहुँचाया गया। घटना का विवरण- जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को विद्यालय में बच्चों को %राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस% या नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई गई थीं। दवा के सेवन के कुछ ही समय बाद, कई बच्चों ने बेचैनी, पेट में दर्द और घबराहट की शिकायत करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। अस्पताल में उपचार जारी- बच्चों की बिगड़ती स्थिति को देख स्कूल प्रशासन ने तुरंत उन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (ष्ट॥ष्ट) पहुँचाया। ष्ट॥ष्ट में प्राथमिक उपचार देने के बाद, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। वर्तमान स्थिति= वर्तमान में करीब एक दर्जन से अधिक बच्चे लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं चिकित्सकीय सहायता= डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चों की निगरानी कर रही है और उनका उपचार जारी है। अभिभावकों में रोष इस घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक अस्पताल और स्कूल पहुँच गए। परिजनों में डर और प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इस बात की जांच कर सकता है कि क्या दवा की डोज में कोई समस्या थी या यह दवा के सामान्य %साइड इफेक्ट्स% (जो कभी-कभी खाली पेट दवा लेने से हो सकते हैं) का मामला है।

सागर ,विदिशा ,लोकसभा सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े क्षेत्र की खुशहाली और सिंचाई हेतु महत्वपूर्ण संवाद

क्यूँ न लिखूँ सच/हाकम सिंह रघुवंशी/ विदिशा / संसद सत्र के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और संगठन के शिल्पी आदरणीय श्री सी. आर. पाटिल जी से भेंट हुई। इस दौरान क्षेत्र के विकास और आगामी कार्ययोजनाओं को लेकर उनसे विस्तृत चर्चा हुई। मुख्य रूप से, केन-बेतवा लिंक परियोजना का विस्तार कर सागर-विदिशा लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में सिंचाई की शत-प्रतिशत सुविधा सुनिश्चित करने हेतु उनसे विशेष आग्रह किया। मेरा लक्ष्य है कि क्षेत्र के हर किसान के खेत तक पर्याप्त पानी पहुँचे और जल संचयन के माध्यम से नई क्रांति आए। आदरणीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में %जल शक्ति% अभियान आज देश में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उनके सकारात्मक आश्वासन और मार्गदर्शन के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ सागर विदिशा लोकसभा सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े

इस महाशिवरात्रि जीवन में पवित्रता व आत्मा को बुराइयों से बचाने का महाव्रत लेना है- ब्रह्माकुमारी रुक्मणी दीदी

क्यूँ न लिखूँ सच/हाकम सिंह रघुवंशी/ विदिशा - गुलाबगंज/ प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा परमपिता परमात्मा की 90 वी त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष पर गुलाबगंज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया महाराष्ट्र से राजयोगिनी संध्या दीदी, विदिशा गरिमामय उपस्थिति में सभी का सम्मान रेखा दीदी ने अपने विचार रखते हुए कहा जन्मदिन के रूप में मनाये जाते है परन्तु %शिवरात्रि% के नाम से पुकारा जाता है। अथवा अयोनि हैं। उनका अन्य किसी जो कि उनका जन्मदिन मनाया जाये। अवतरित होते हैं। उनकी जयंती संज्ञावाचक अवतरण विषय-विकारों की कालिमा से परमात्मा शिव द्वारा इस %अज्ञान रूपी रात्रि% कहा जाता है। महाराष्ट्र से आए हुए संध्या अनोखी बात यह है कि इसका सम्बन्ध

जिसमें मुख्य रास्तों से दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई, कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुकेश टंडन व अन्य गणमान्य नागरिकों की के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ब्रह्माकुमारी कि विश्व की सभी महान विभूतियों के जन्मोत्सव प्राय: दिन के समय एक परमात्मा शिव की जयंती ही ऐसी है जिसे जन्मदिन न कहकर इसका कारण यह है कि निराकार परमात्मा शिव जन्म-मरण से न्यारे महापुरुष या देवता की तरह कोई लौकिक या शारीरिक जन्म नहीं होता कल्याणकारी विश्व पिता शिव तो अलौकिक अथवा दिव्य-जन्म लेकर नहीं, बल्कि कर्तव्यवाचक रूप से ही मनाई जाती है। उनका दिव्य लिप्त अज्ञान निद्रा में सोये हुए मनुष्य को जगाने के लिये ही होता है। का अंत किये जाने के आध्यात्मिक रहस्य से ही शिव जयंती को शिवरात्रि दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि महाशिवरात्रि के सम्बन्ध में सबसे निराकार, अशरीरी परमात्मा से है। जबकि अन्य सभी त्योहारों, पर्वो अथवा जयन्तियों का देवताओं, पौराणिक महापुरुषों के जीवन से सम्बन्ध होता है। अत: शिवरात्रि परमात्मा शिव के इस धरा पर अवतरण की यादगार है। परमात्मा शिव, सामान्य मनुष्यों की तरह शरीरधारी नहीं हैं और जन्म-मरण के बन्धनों से मुक्त है। गीता में भगवान ने इस सम्बन्ध में कहा है जो मुझे मनुष्यों की भांति जन्म लेने और मरने वाला समझते हैं वे मूढ़मति हैं (अध्याय 6, श्लोक 24, 25)। पुन: वे कहते हैं मेरे दिव्य जन्म के रहस्य को न महर्षि, न देवता जानते हैं (अध्याय 10, श्लोक 2)। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा प्रकृति के तत्वों के अधीन कोई सामान्य मनुष्यों की तरह शरीरधारी नहीं हो सकता है। प्राय: सभी धर्मों के लोग निर्विवाद रूप से परमात्मा को ज्योतिबिन्दु स्वरूप और अशरीरी तथा जन्म-मरण रहित% तो स्वीकार करते ही हैं। अत: शिव का अन्य भाषान्तर %गॉड%, खुदा ओंकार इत्यादि है और शिवरात्रि परमात्मा के दिव्य-अवतरण दिवस की यादगार है। ब्रह्माकुमारी रुक्मणी दीदी ने अपनी भावनाएं रखते हुए कहा कि इसका आध्यात्मिक यथार्थ रहस्य यह है कि वर्तमान संगमयुग पर मनुष्यात्माओं को पावन बनाने के लिए परमात्मा शिव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कुसंस्कार एवं आसुरी प्रवृत्तियों का दान ले रहे हैं। इन सूक्ष्म मनोविकारों को मानसिक रूप से परमात्मा शिव के सम्मुख अर्पण करके जीवन में पवित्रता और आत्मा को बुराइयों से बचाने का महाव्रत लेना है तभी हमारे जीवन में सुख-शान्ति एवं दिव्य-गुणों की सच्ची धारणा हो सकती है एवं परमात्मा शिव से हम अपने पुरुषार्थ अनुसार जन्म-जन्मान्तर के लिए ईश्वरीय राज-भाग्य का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इस सृष्टि पर निराकार ज्योतिर्बिन्दु स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव अवतरित हो चुके हैं। सृष्टि चक्र के ड्रामानुसार वे साकार मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सर्व मनुष्यात्माओं को हार्दिक ईश्वरीय निमन्त्रण है कि परमात्मा शिव द्वारा दिये जा रहे इस ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण कर जन्म-जन्मान्तर के लिए श्रेष्ठ राज-भाग्य को प्राप्त करें। विधायक मुकेश टंडन जी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन होते रहे जिससे सभी में आध्यात्मिकता की जागृति बनी रहती है व ब्रह्मा कुमारीज के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू की महिमा की, राकेश कटारे जी ने कहा कि गुलाबगंज के चारों ओर धार्मिक व आध्यात्मिकता की लहर फैली हुई है इसका श्रेय ब्रह्माकुमारी बहनों को जाता है। अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखें व अधिक संख्या में भाई बहनों ने कार्यक्रम का लाभ लिया।

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए
9027776991
knlslive@gmail.com

First, career set, then 'baby steps': Why are women deciding to become mothers after the age of 30?

Motherhood isn't just a word, it's a huge responsibility. Therefore, thorough preparation is required. For this, even delaying motherhood after a late marriage isn't a big deal. A recent report provides a strong indication of this shift in society. This wave of change is now reaching from metropolitan cities to smaller towns. Seema Jha spoke with some young women and experts about this... Women are prioritizing career and financial stability. In today's times, women are adopting options like IVF. Due to the increase in the average age of marriage, delayed motherhood is common. Just a year after marriage, everyone in the in-laws' house started asking, "When will you plan a baby?" But I wasn't ready for one yet, so I remained silent. Avantika Sharma, 32, working in Noida, is among those women for whom the calendar is important. She keeps wondering when her career will be set and when she will be financially independent, but the body's biological calendar is different. This is where the challenges begin. While they may face obstacles in fulfilling their desire to have a child right now, they are prepared to face these challenges, knowing all this. Data from recent years confirms that women are now deciding to become mothers after the age of 30. They understand the challenges, but they have options that help reduce their anxiety. Recently, South Indian actor Ram Charan's wife, Upasana Kamineni, came under attack from trolls when she advised women to freeze their eggs at a session at IIT Hyderabad. However, she responded to their questions with questions: Is it wrong for a woman to decide when she wants a child based on her circumstances? Is it wrong to set goals and focus on her career, rather than simply thinking about marriage or having children soon? Discomfort with change: During the process of social change, sometimes things happen that are quite uncomfortable. Parents who fully support their daughters in their studies and careers seem reluctant to have children late in life because of social pressure. As Priya says, "I pursued my studies on my own. After getting a job, my family asked me to get married, and I got married." Up until this point, my parents were completely supportive, but I felt bad when, just a few months into marriage, they started insisting on having a child. According to Priya, if my parents supported me in every decision, why weren't they supportive in my decision to become a mother? Avantika also says, "As soon as a year of marriage was over, my child's insistence on it made me feel a little uncomfortable at my in-laws' house. To avoid arguments, I put the matter to my husband, and I felt a little more at ease." In this context, Dr. Pratima Gond says, "Society is going through a transition. At this time, things are naturally in the process of improving." The concrete reasons are: Traditional thinking about girls' marriage and motherhood, that is, marriage at the age of 20-22 and motherhood by the age of 24, is considered ideal." This belief is now being challenged, but there are some solid reasons for it. As Priya says, our generation has witnessed the pain and struggle of the previous generation in raising children. They understand the challenges faced by those who are not financially strong. Furthermore, the challenges faced by working women after becoming mothers can be added to this. Working women sometimes have to leave important projects, sometimes even their jobs. Priya also says that the children of working mothers can easily understand that only through hard work can they achieve their dreams, and later, after their own struggles, they can be proud of their successful parents. According to Avantika, the most important thing is that when we are not mentally prepared, how can a big decision like having a child be a good one? She says that the support system in the family is also weakening. We have to raise the child, not our parents. Therefore, the decision to have a child should be in our favor. This task should be made easier – financial independence is the biggest dimension of women's empowerment. According to Dr. Pratima, economic independence is somewhat selective in our country. A job is fine, but unlike in Japan and Korea, self-employment isn't prioritized. This puts pressure on girls to find well-paying jobs. As Priya says, one must not only do a job but also do it well, and this takes time. In such a situation, becoming a mother becomes a significant task, as girls now want to plan their entire life before and after pregnancy. Work pressure, deadline stress, and other factors pose challenges to motherhood. Regarding this, gynecologist Dr. Manju Puri says that many factors can lead to pre-pregnancy problems, but they are now aware of them. The growing business of IVF and the trend of egg freezing is making it easier to become a mother at an older age. Picture in figures According to the 2023 Sample Registration Survey Statistics Report of the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India: The average age of marriage for women has increased from 22.1 years in 2019 to 22.9 years in 2023. In urban India, more than four out of five women now marry after the age of 21, reducing the years available for childbearing. In states like Kerala, Himachal Pradesh and Haryana, most women marry late and have children. It also reduces fertility. Pressure will worsen things. Girls have learned from observing their mothers, grandmothers, and others how painful it can be to not make decisions of their choice. Such decisions, made under social pressure, can anger their prospective partner, even their child, and negatively impact the relationship. If they are afraid or feel pressured, they should consult a counselor or family member. - Srishti Asthana Bisht, Psychologist. Be supportive of your partner - If you want to experience the joy of motherhood and advance in your career, keep these things in mind. Don't neglect your health. Before marriage, have clear thoughts with your prospective partner about everything from marriage to family planning and parenting your future child. - Priya Saraswat, Content Moderator, Amazon, Bengaluru. The new generation is more mature - The new generation doesn't like to show off or live in frustration. They understand the importance of being emotionally mature and prepared. When society can't change something, it offers alternatives. Therefore, in the corporate world, mothers are now offered the option of crèches and childcare. Policymakers are also becoming increasingly sensitive to new mothers. - Dr. Pratima Gond, Associate Professor, Sociology, BHU According to the Delhi government's annual birth and death registration report for 2024, 8.9 percent of births that year were born to mothers aged 35 or older.

AI-enabled 'digital stethoscopes' will make TB diagnosis easier, with millions of patients expected to benefit.

TB remains one of the deadliest infectious diseases worldwide, but artificial intelligence has now brought a new revolution to the medical field. A recent study has revealed that AI-enabled 'digital stethoscopes' could prove to be a powerful tool in addressing the shortcomings of TB diagnosis. Millions of TB patients remain unmet by existing screening programs. The AI ??digital stethoscope detects TB through subtle sounds, making TB testing accessible in remote areas. TB remains the leading cause of death from infectious diseases worldwide, but even more alarming is the fact that millions of patients remain undiagnosed. A frightening statistic from the World Health Organization (WHO) reveals that approximately 2.7 million TB patients are overlooked by current screening programs. Amidst this serious problem, science has shown a new ray of hope—and that is the "digital stethoscope with artificial intelligence." According to a new study, this smart technology is capable of saving lives even in remote areas where healthcare facilities are not easily accessible. Millions of patients remain undiagnosed. World Health Organization (WHO) data shows that due to the limitations of current screening programs, approximately 2.7 million TB patients remain undiagnosed. Sometimes, the symptoms of the disease are unclear, or testing facilities are expensive and not available everywhere. This leads to patients not being identified in a timely manner, which can now be improved with new technology. How does this stethoscope work? According to a report published in the journal Med, AI technology is capable of identifying subtle sounds (sound biomarkers) of the disease that the human ear cannot hear. This digital stethoscope analyzes sounds coming from the lungs during coughing and breathing, which may seem normal but are actually signs of disease. This is called 'auscultation,' and AI will now assist doctors. A great alternative to expensive machines: Until now, ultra-portable radiography and computer software have been recommended by the WHO for diagnosing TB. However, these machines are expensive and radiation exposure makes them difficult for pregnant women to use. Researchers believe that AI digital stethoscopes are a cheaper and safer alternative, potentially useful in remote areas where X-ray machines are inaccessible. Successful studies in several countries, including India: Researcher Madhukar Pai of McGill University in Canada and other global experts reported that this technology has demonstrated high accuracy in detecting lung and heart diseases. Studies conducted in high-TB countries such as India, Peru, South Africa, Uganda, and Vietnam have found it to be highly effective. It is yielding positive results not only in early detection of TB but also in other diseases. Hope for the future: Experts say this technology has the potential to fill a significant gap in TB screening. It needs to be tested on more patients in different environments to make it more effective, but it is clear that the AI ??digital stethoscope could be a game-changer in bringing equality to healthcare and finding hidden TB patients.

After theaters, Mana Shankara Vara Prasad Garu will hit the OTT platform. When and where will Chiranjeevi's film release?

Did you miss Mana Shankara Vara Prasad Garu in theaters? No worries, now you can enjoy it on OTT. Let's find out when and where. When and where will Chiranjeevi's film release on OTT? Mana Shankara Vara Prasad Garu was released on January 12th - the film will stream on OTT on this day. Chiranjeevi starrer Mana Shankara Vara Prasad Garu released in theaters on January 12th, 2026, on the occasion of Sankranti this year. If you missed watching it in theaters for some reason, you can now stream it on OTT. Let's find out when and where will the film release? What is the story? - Mana Shankara Vara Prasad Garu is the story of Shankara Varaprasad, a National Security Officer working in the NIA. He is married to Sasirekha, the daughter of India's richest man. The two fall in love, even against their father's wishes, as Varaprasad comes from a middle-class background. Over time, Sasirekha's father creates difficulties in their married life, leading to numerous challenges. After several misunderstandings, the couple has been living separately for six years, causing turmoil in Varaprasad's personal life. As Shankara Varaprasad faces these challenges in an attempt to mend his broken relationship and reunite with his wife, an old enemy from his past resurfaces, posing a threat to his family's safety. To find out how Varaprasad handles these challenges and whether he is able to reunite with his wife and children, you will have to watch the film. When and where will the film release? Mana Shankara Varaprasad Garu is scheduled to release on the OTT platform ZEE5 and will begin streaming on February 11, 2026. This official update was shared through the social media handles of the OTT platform. Cast and crew of Mana Shankara Vara Prasad Garu - Mana Shankara Vara Prasad Garu stars Chiranjeevi in ??the lead role. Apart from the megastar, the film also stars Nayanthara, Catherine Tresa, Zarina Wahab, Harsh Vardhan, Abhinav Gomatam, Sachin Khedekar, Sharat Saxena, Sudev Nair and many others in pivotal roles. Additionally, Venkatesh Daggubati appears in a cameo role.

Makers bow out amid protests; will Manoj Bajpayee's film's name be changed?

Manoj Bajpayee's upcoming film "Ghuskhor Pandit" is facing significant backlash due to its title. A legal notice was also sent to Netflix, and now Neeraj Pandey has issued an official statement regarding the matter. Makers issue notice to Netflix over the "Ghuskhor Pandit" controversy. Official statement: Makers will remove all promotional material. Manoj Bajpayee's Netflix film "Ghuskhor Pandit" was part of a major announcement by the streaming giant. The actor plays a police officer with no conscience and no remorse. We only get a glimpse of his world and the people around him. Opposition to the film's title: However, the Brahmin community did not like the name, finding it offensive. Following the announcement, a petition was filed against the film in the Delhi High Court. The petition, filed by Mahendra Chaturvedi through advocate Vineet Jindal, seeks a writ of mandamus directing authorities to stop the streaming of the film. Makers release official statement - Now, filmmaker Neeraj Pandey has released an official statement, in which he wrote, "Our film is a fictional cop drama, and the word 'Pandit' is used only as a colloquial term for a fictional character. The story focuses on the actions and decisions of one individual and does not comment on or represent any caste, religion, or community. As a filmmaker, I approach my work with great responsibility to tell stories that are thoughtful and respectful." He further added, "This film, like my previous works, has been made with good intentions and solely for the entertainment of the audience. We understand that the title of the film has hurt some viewers, and we truly understand those sentiments." Given these concerns, we have decided to remove all promotional material for now, as we believe the film should be viewed in its entirety to understand the story we wanted to tell, rather than judged by incomplete parts. I look forward to sharing the film with audiences soon." Legal notice issued to Netflix - A Mumbai lawyer has sent a legal notice to Netflix and the directors of the upcoming film "Ghooskhor Pandat." The notice alleges that the use of the word "Pandit" in association with corruption is defamatory and a direct attack on the dignity of a community. Manoj Bajpayee plays the role of Pandit - This notice comes shortly after the teaser of "Ghooskhor Pandit" was launched at a public event. In this project, actor Manoj Bajpayee plays Senior Inspector Ajay Dixit, who is shown in the teaser as a disgraced Delhi police officer known as Pandit. The teaser reveals that Dixit joined the police force as a sub-inspector 20 years ago but is stuck at the same rank. Legal notice sent to Netflix - This legal notice has been sent by advocate Ashutosh Dubey, who has demanded the immediate withdrawal of the title and called it "defamatory, defamatory to the community, unconstitutional and socially inflammatory." According to the notice, the title 'Bhuskhor Pandit' is "self-defamatory" and objectionable because it conflates a word associated with bribery and corruption with the word Pandit, which Dubey described as a historically respected cultural, religious and intellectual identity.

Shahid Kapoor and Rashmika Mandanna bag another big film before the release of Cocktail 2; shooting to begin soon

Shahid Kapoor and Rashmika Mandanna will be seen together in Amit Sharma's next romantic comedy after "Cocktail 2." Amit Sharma, director of "Maidaan" and "Badhaai Ho," will direct the film, which is expected to begin shooting in August-September 2026. "O Romeo" will release on February 13th. Shahid Kapoor and Rashmika will be seen in Amit Sharma's film - Actor bags Amit Sharma's film Shahid Kapoor and Rashmika Mandanna will soon be seen in Cocktail 2. The film is scheduled to release in September this year, but before that, the pair has secured a new project. According to Variety, director Amit Sharma has finalized Shahid and Rashmika for his next romantic comedy. Both actors recently completed shooting for "Cocktail 2." Rashmika Mandanna will also be seen in this movie with him. Amit Sharma will be the director of the film - The film will be directed by Amit Sharma, known for films like 'Maidaan' and 'Badhaai Ho'. It will be produced by Sunir Khetarpal under the Vermilion World banner in association with Jio Studios. The title of the film has not been decided yet. However, according to one estimate, Shahid and Rashmika will start shooting for their next project in August-September 2026 after completing their current projects. When will 'O Romeo' release? Shahid Kapoor is currently excited about his upcoming action-thriller, 'O Romeo', which is scheduled to release on February 13th. The film will star Tripti Dimri, Nana Patekar, Avinash Tiwari, Tamannaah Bhatia, Disha Patani, Farida Jalal, and Vikrant Massey. Vishal Bhardwaj is the director of this film. After this, the actor will soon start shooting for 'Farzi' on Amazon Prime Video. Meanwhile, Rashmika Mandanna has several projects in the pipeline, including "Ranbali" with Vijay Deverakonda and Atlee's action film "#AA22xA6." She also has "Maisa" in the pipeline.